एस.एस. संधावालिया, सी.जे. और पी.सी. जैन से पहले, जे.

भीम सिंह, अपीलकर्ता।

बनाम

ग्राम खरखेड़ी की ग्राम पंचायत और अन्य,-प्रतिवादी^

1973 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 1710।

मैं 7 अप्रैल 1983.

पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट (1961 का XVIII) - धारा 13 - सिविल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री - ऐसे डिक्री के खिलाफ अपील लंबित - सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार पूर्वव्यापी रूप से वर्जित - का प्रभाव।

माना गया कि धारा 13 के अवलोकन से पता चलता है कि उपरोक्त प्रावधान के लागू होने के बाद, सिविल कोर्ट के पास भूमि की शामलात प्रकृति से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विचार करने या निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। केवल इस तथ्य से कि 1981 के अधिनियम 2 के लागू होने से पहले एक सिविल कोर्ट द्वारा एक डिक्री पारित की गई थी, जिसके द्वारा धारा 13 को प्रतिस्थापित किया गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपील की अदालत भी एक सिविल कोर्ट है और उसके पास समान शक्तियां हैं और वह लगभग सभी के समान कार्य करती है। जैसा भी हो, वही कर्तव्य हैं जो मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों पर सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रदान और लगाए गए हैं। • यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि एक बार अदालत द्वारा पारित डिक्री के खिलाफ अपील की गई तो मामला फिर से विचाराधीन हो जाता है और उसके बाद अपीलीय अदालत पूरे मामले पर विचार करती है। कानून का यह भी अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि किसी अपील की सुनवाई इस देश के प्रक्रियात्मक कानून के तहत, पुनः सुनवाई की प्रकृति में होती है और अपील की अदालत उन तथ्यों और घटनाओं को भी ध्यान में रखने की हकदार है। डिक्री के विरुद्ध अपील के बाद अस्तित्व में आया। अधिनियम की धारा 13' के तहत, एक सिविल न्यायालय को न केवल किसी मुकदमे पर विचार करने से, बल्कि भूमि की शामलात प्रकृति से संबंधित किसी भी प्रश्न पर निर्णय देने से भी रोक दिया गया है। यदि अपीलीय न्यायालय, जो कि एक सिविल न्यायालय है, को विवाद को एक या दूसरे तरीके से निर्धारित करने की अनुमति दी जाती है, तो यह सिविल न्यायालय को ऐसे मामले का निर्धारण करने और निर्णय लेने की अनुमति देगा जिस पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। . यह कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है. मामले के इस दृष्टिकोण में, मेरा मानना है कि ऐसे मामलों में जहां सिविल कोर्ट की डिक्री अंतिम नहीं हुई है और मामला अभी भी अपील में लंबित है, तो इस सवाल पर कि क्या भूमि शामलात देह है या नहीं, सिविल कोर्ट को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। मनोरंजन करें और उस प्रश्न पर निर्णय लें। (पैरा 6).

(इस मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए 17 मार्च, 1983 को माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन द्वारा मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा गया था। बड़ी पीठ में माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. संधावालिया शामिल थे। और माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन ने अंततः 7 अप्रैल, 1983 को मामले का फैसला किया)।

श्री राजेंद्र लाल गर्ग, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव की अदालत के 26 सितंबर, 1973 के फैसले से नियमित दूसरी अपील, श्री मान सिंह सैनी, उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, गुड़गांव की पुष्टि

दिनांक 17 अप्रैल, 1973 ने वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया।

अपीलकर्ताओं के लिए एन.सी. जैन, अधिवक्ता और एस.एस. जैन, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से एम. एस. लिब्रहान, वकील।

प्रलय

प्रेम चंद जैन, जे.-

(1) भीम सिंह और अन्य, वादी, ने प्रतिवादियों को गांव खरखेड़ी, तहसील और जिला गुड़गांव में आयत संख्या 11 के किला संख्या 25 मिनट में शामिल भूखंड पर उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया। मुकदमा ग्राम पंचायत द्वारा इस आरोप पर लड़ा गया था कि विवादित संपत्ति ग्राम पंचायत और सिविल कोर्ट में निहित है, जिसके पास मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने पूरे मामले पर विचार करने के बाद माना कि वाद वाली भूमि ग्राम पंचायत में निहित है। हालाँकि, क्षेत्राधिकार के सवाल पर, ट्रायल कोर्ट ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि चूंकि वादी ने यह स्वीकार नहीं किया कि यह भूमि शामलात देह थी, इसलिए, स्वामित्व का प्रश्न होने के कारण, सिविल कोर्ट के पास मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र था। चूंकि वादी को विवाद में संपत्ति का मालिक नहीं पाया गया, मुकदमा 17 अप्रैल, 1973 को ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था।

(2) ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री से व्यथित महसूस करते हुए, वादी ने एक अपील दायर की, जिसे 26 सितंबर, 1973 को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव ने खारिज कर दिया। फिर भी असंतुष्ट होकर वर्तमान नियमित दूसरी अपील दायर की गई है वादीगण द्वारा.

(3) अपील 17 फरवरी 1983 को मेरे समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आई। अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री एन.सी. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह था कि सिविल कोर्ट को इस पर निर्णय देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। प्रश्न करें कि क्या वाद भूमि शामलात देह है और ग्राम पंचायत में निहित थी या नहीं। इस स्थिति में, विद्वान वकील के अनुसार, निचली अदालतों के निर्णयों और डिक्री को रद्द करना पड़ा और धारा 13 के तहत सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वादी को वादी को वापस करना पड़ा। -पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (विनियमन) अधिनियम, 1961 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) का ए। के निर्णय के रूप में

उपरोक्त विवाद बजिंदर सिंह और अन्य बनाम सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, गुहला (1) मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले की व्याख्या पर निर्भर था, मैंने निर्णय के लिए मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला किया। इस तरह हम मामले को समझ गए हैं।

(4) शुरुआत में यह देखा जा सकता है कि वादी के विद्वान वकील श्री एन.सी. जैन के उपरोक्त तर्क का उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री एम.एस. लिब्रहान ने खंडन नहीं किया था। हालाँकि, हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील के तर्क पर स्वतंत्र रूप से भी विचार किया है और उसमें योग्यता पाई है।

(5) विवाद का उचित निर्णय करने के लिए इसका पता लगाना आवश्यक है

इस प्रावधान का विधायी इतिहास. जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, अधिनियम की धारा 13 निर्धारित करती है कि किसी भी सिविल न्यायालय के पास उक्त अधिनियम के संचालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। जाहिर तौर पर, सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक की प्रकृति के संबंध में न्यायालयों द्वारा की गई व्याख्या के परिणामस्वरूप, विधानमंडल ने पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन), हरियाणा अधिनियम 34 द्वारा इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया। 1974 का अधिनियम, जो 12 नवंबर, 1974 को लागू हुआ। इस संशोधन के आधार पर, मूल धारा 13 को प्रतिस्थापित किया गया और दो नए खंड, अर्थात् धारा 13-ए और 13-बी को अधिनियम में जोड़ा गया। इन संशोधनों को इस न्यायालय में द करनाल को-ऑपरेटिव फार्मर्स सोसाइटी लिमिटेड बनाम ग्राम पंचायत पेहोवा और अन्य (2) मामले में चुनौती दी गई थी। डिवीजन बेंच एक विस्तृत फैसले में इस निष्कर्ष पर पहुंची कि धारा 13-ए की उप-धारा (3) अधिकारातीत है और चूंकि उक्त धारा के अन्य प्रावधान उसी के इर्द-गिर्द घूमते हैं, इसलिए, पूरी धारा, असंवैधानिक था और परिणामस्वरूप उसे हटा दिया गया। उस निर्णय में यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 13-बी की शक्तियों को कोई चुनौती नहीं दी गई थी। हरियाणा राज्य ने स्पष्ट रूप से उक्त निर्णय को स्वीकार कर लिया और इसके खिलाफ अपील नहीं की। हालाँकि, एक आवश्यक परिणाम के रूप में, इसने 1981 के पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) हरियाणा संशोधन अधिनियम संख्या 2 को अधिनियमित किया, जहां- मौजूदा धारा 13 में पर्याप्त बदलाव किए गए और जैसा कि पहले ही देखा गया था, इन्हें पूर्वव्यापी रूप से पेश करने की मांग की गई थी। यानी, 4 मई, 1961 से। इसी तरह, मौजूदा धारा 13-ए और

(1) 1983 पी.एल.जे. 116.

(2) 1976 पी.एल.जे. 237.

12 नवंबर, 1974 से 13-बी को क़ानून की किताब से हटा दिया गया और 4 मई, 1961 से नई धाराएँ 13-ए, 13-बी, 13-सी और 13-डी को पूर्वव्यापी रूप से शामिल किया गया। 4 मई, 1961 से काल्पनिक प्रतिस्थापन यह था कि सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा वैध रूप से पारित सभी आदेश रद्द कर दिए गए। नतीजतन, धारा 13 की संवैधानिक वैधता उस हद तक है जिसके परिणामस्वरूप सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का पूर्वव्यापी निरसन हुआ, जो कि वैध रूप से प्रयोग किया गया था, बजिंदर सिंह के मामले (सुप्रा) में विचार के लिए आया था। पूरे मामले पर विचार करने के बाद, बेंच ने धारा 13 के प्रावधानों को रद्द कर दिया, जहां तक इसकी पूर्वव्यापी प्रकृति का सवाल था। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

"उपरोक्त विस्तृत कारणों से पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) हरियाणा अमेंडमेंट एक्ट 1981 की विवादित धारा 4 द्वारा 1961 के बाद से उनके द्वारा वैध रूप से प्रयोग किए जाने वाले सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को पूर्वव्यापी रूप से निरस्त करना, स्पष्ट रूप से एक खाई के समान है। विधायिका द्वारा न्यायिक शक्ति. नतीजतन, उपरोक्त धारा का प्रासंगिक हिस्सा 4 मई, 1961 से धारा 13 को काल्पनिक रूप से प्रतिस्थापित करता है, और इस प्रकार उक्त तिथि से पूर्वव्यापीता देता है।

इसे असंवैधानिक माना जाता है और इसके द्वारा इसे रद्द कर दिया जाता है।"

(6) जिस प्रश्न पर अब निर्णय की आवश्यकता है वह यह है कि धारा 13 का उस डिक्री पर क्या प्रभाव पड़ता है जो सिविल न्यायालय द्वारा वैध रूप से पारित किया गया है लेकिन जिसके खिलाफ अपील की गई है। धारा 13 की भाषा और विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के आलोक में, जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था, स्पष्ट उत्तर यह है कि सिविल न्यायालय के पास ऐसे मामलों पर निर्णय देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अधिनियम की धारा 13 इस प्रकार है: -

"13. क्षेत्राधिकार की वर्जना - किसी भी सिविल न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार नहीं होगा -

(ए) किसी भी प्रश्न पर विचार करना या निर्णय देना चाहे-

(i) कोई भी भूमि या अन्य अचल संपत्ति शामलात देह है या नहीं है;

(ii) कोई भी भूमि या अन्य अचल संपत्ति या ऐसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति में कोई अधिकार, शीर्षक या हित इस अधिनियम के तहत पंचायत में निहित है या निहित नहीं है;

(बी) किसी भी मामले के संबंध में जिसे निर्धारित करने के लिए कोई राजस्व न्यायालय, अधिकारी या प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत या इसके तहत सशक्त है; या

(सी) इस अधिनियम के तहत ऐसा करने के लिए सशक्त किसी राजस्व न्यायालय, अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या निर्णय किए गए मामले की वैधता पर सवाल उठाना।

उपरोक्त धारा के अवलोकन से पता चलता है कि उपरोक्त प्रावधान के लागू होने के बाद सिविल कोर्ट के पास भूमि की शामलात प्रकृति से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विचार करने या निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। केवल इस तथ्य से कि 1981 के अधिनियम 2 के प्रवर्तन से पहले एक सिविल कोर्ट द्वारा एक डिक्री पारित की गई थी, जिसके द्वारा धारा 13 को प्रतिस्थापित किया गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपील की अदालत भी एक सिविल कोर्ट है और उसके पास समान शक्तियां हैं और वह लगभग सभी के समान कार्य करती है। जैसा भी हो, वही कर्तव्य हैं जो मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालयों पर सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रदान और लगाए गए हैं। कानून का यह अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि एक बार अदालत द्वारा पारित डिक्री के खिलाफ अपील की गई तो मामला फिर से विचाराधीन हो जाता है और उसके बाद अपीलीय अदालत पूरे मामले को अपने कब्जे में ले लेती है। कानून का यह भी अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि किसी अपील की सुनवाई इस देश के प्रक्रियात्मक कानून के तहत, पुनः सुनवाई की प्रकृति में होती है और अपील न्यायालय उन तथ्यों और घटनाओं को भी ध्यान में रखने का हकदार है। डिक्री के विरुद्ध अपील के बाद अस्तित्व में आया। इस संबंध में अमर जीत कौर बनाम प्रीतम सिंह और अन्य (3) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखें। जैसा कि पहले देखा गया है, अधिनियम की धारा 13 के तहत, एक सिविल कोर्ट को न केवल एक मुकदमे पर विचार करने से, बल्कि भूमि की शामलात प्रकृति से संबंधित किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने से भी रोक दिया गया है। यदि अपीलीय न्यायालय, जो कि एक सिविल न्यायालय है, को विवाद को एक या दूसरे तरीके से निर्धारित करने की अनुमति दी जाती है, तो यह सिविल न्यायालय को विवाद का निर्धारण करने और निर्णय लेने की अनुमति देगा।

वह मामला जिस पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है. मामले के इस दृष्टिकोण में, मेरा मानना है कि ऐसे मामलों में जहां सिविल कोर्ट की डिक्री अंतिम नहीं हुई है और मामला अभी भी अपील में लंबित है, तो इस सवाल पर कि क्या भूमि शामलात देह है या नहीं, सिविल कोर्ट को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। उस प्रश्न पर विचार करें और निर्णय दें। मेरे इस दृष्टिकोण को ग्राम सभा बलाद कलां में एक डिवीजन बेंच के फैसले से समर्थन मिलता है

(3) 1974 पी.एल.जे. 406.

अन्य बनाम सरवन सिंह और अन्य (4) और लालजी सिंह और अन्य बनाम ग्राम सभा, लाहली और अन्य (5) और ग्राम पंचायत सधरौर बनाम बलदेव सिंह और अन्य (6) में एकल पीठ के फैसले।

(7) अन्य कोई बिन्दु विचार हेतु उपस्थित नहीं होता।

(8) ऊपर दर्ज कारणों से मैं इस अपील को स्वीकार करता हूं, नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों और डिक्री को रद्द करता हूं और निर्देश देता हूं कि अधिनियम के तहत गठित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इसे प्रस्तुत करने के लिए वादी को वादी को वापस कर दिया जाए। मामले की परिस्थितियों में, मैं लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देता।

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.-मैं सहमत हूं।

एस.सी.के. „

एस.एस. कांग और जी.सी. मितल से पहले, जे.जे.

ऋषि दत्त गुलाटी और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1983 की सिविल रिट याचिका संख्या 474।

11 अप्रैल, 1983.

पंजाब नगर सुधार अधिनियम (1922 का चतुर्थ) (1982 के पंजाब अधिनियम 18 द्वारा संशोधित) - धारा 3, 3-ए, 4 और 103 - नया ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव है लेकिन धारा 3-ए के तहत अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है - नगरपालिका आयोग हालाँकि, समिति ने प्रस्तावित ट्रस्ट के लिए तीन सदस्यों को ट्रस्टी के रूप में चुनने के लिए कहा था, लेकिन नगरपालिका समिति ने ऐसा नहीं चुना - धारा 3-ए के तहत एक नया ट्रस्ट बनाने की अधिसूचना जारी की गई - नगरपालिका समिति को इसके बाद ट्रस्टी चुनने का मौका नहीं दिया गया। ट्रस्ट का निर्माण - ऐसे ट्रस्टियों का चुनाव करने के लिए समिति की कथित चूक के लिए सरकार धारा 4(4) के तहत तीन ट्रस्टियों की नियुक्ति करती है - सरकार द्वारा ट्रस्टियों की नियुक्ति - चाहे अमान्य हो।

(4) 1981 पी.एल.जे. 311.

(5) 1982 पी.एल.जे. 140.

(6) 1983 पी.एल.जे. 19.

स्थानीय : भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है तांकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उददेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अर्शवीर कौर संधू
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा